लक्ष्य और उपलब्धियां

प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2015 का संबोधन

पूरे किए गए वादे - उपलब्धि

15 अगस्त, 2015 को प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस संबोधन

क्र. स.	वादे	उपलब्धि
1.	**प्रधानमंत्री जनधन योजना** मेरे देशवासियों, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमने नियत समय सीमा के अंदर वह लक्ष्य हासिल कर लिया है। 17 करोड़ लोगों ने 'प्रधानमंत्री जनधन योजना' के अंतर्गत अपने बैंक खाते खोले हैं। गरीबों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हमने कहा था कि ये बैंक खाते जीरो बैलेंस से खोले जा सकते हैं। हमने यह भी कहा था कि हम बैंकों की संचालन लागतों का वहन करेंगे। आखिरकार बैंक किसलिए हैं? बैंकों को गरीबों के लिए होना चाहिए और इसीलिए हमने जीरो बैलेंस के साथ खाते खोलने का निर्णय लिया था। हम अपने देश की पहुंच को	• पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 19 जुलाई, 2017 तक कुल 29.18 करोड़ खाते खुले। इसमें से 19.07.2017 को ग्रामीण क्षेत्रों में 17.45 करोड़ खाते खोले गए। • शहरी क्षेत्रों में पीएमजेडीवाई खातों की संख्या 19.07.2017 तक : 11.73 करोड़ • 22.35 करोड़ रूपे कार्ड जारी किए गए (19 जुलाई, 2017 तक) • सक्रिय खातों में 15.77 करोड़ आधार से जुड़े (असम और मेघालय को छोड़कर)। जनधन खातों में कुल जमा राशि 64,777 करोड़ रुपये (19.07.2017 तक)

	देख चुके हैं लेकिन अबकी बार हमने अपने गरीब लोगों और उनके धन को देखा है।	
2.	**सर्वोधिक गरीब के लिए सामाजिक सुरक्षा** यह देश को तेजी से विकास की ऊंचाइयों पर ले जाती है और इसलिए हमारा इरादा इसे गति देने का है। हमने सामाजिक सुरक्षा और गरीब के कल्याण पर भी बहुत अधिक बल दिया है और इस तरह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लांच की गई है। अपने देश के करोड़ों लोगों को किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा कवर नहीं है। गरीब को अलग रखें तो बीमा का लाभ निम्न मध्यम वर्ग तक भी नहीं पहुंचा है। इसलिए हमने एक योजना बनाई - हर महीने केवल एक रुपया दें, इससे अधिक नहीं, यह प्रतिवर्ष 12 रुपये होता है और इससे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ लेने का पात्र बनें। यदि आपका परिवार किसी आपदा का सामना कर रहा है तो उसे 2 लाख रुपये प्राप्त होंगे। हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को किस तरह से प्रबंधित किया जा सकता है। इसीलिए हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक दिन में 90 पैसे से शुरू की। 1 रुपये से भी कम में। इस तरह किसी परिवार के स्वास्थ्य	**प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)** • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना(पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत 27.07.2017 तक 1,02,020,812 व्यक्तियों का नामांकन। • 27.07.2017 तक प्राप्त दावों की कुल संख्या 1,51,42 रही। • 27.07.2017 तक 1,12,24 दावों का निस्तारण प्रति वर्ष 12 रूपये में दुर्घटना योजना बीमा **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)** • 27.07.2017 तक पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत 31,556,755 व्यक्तियों का नामांकन • 27.07.2017 तक प्राप्त दावों की कुल संख्या 72,110 रही। • 27.07.2017 तक 67175 दावों का निस्तारण। केवल 330 रूपये प्रति वर्ष में जीवन बीमा **अटल पेंशन योजना (एपीवाई)**

	के लिए यह 330 सालाना होता है और परिवार की सुरक्षा के लिए 2 लाख रुपये का बीमा होता है। यह काम हमने किया है।	• 22 जुलाई, 2017 को संचित उपभोक्ताओं की कुल संख्या 5,825,024 रही जो एपीवाई के अंतर्गत नामांकित हैं। 2017-18 के दौरान एपीवाई के अंतर्गत आवटित धनराशि 155 करोड़ रुपये (बजट अनुमान)
3.	**स्वच्छ भारत** करोड़ों ऐसे परिवार भारत में हैं जिनके बच्चे 5, 10 और 15 वर्ष की उम्र के हैं और ये बच्चे 'स्वच्छ भारत' अभियान के बड़े एंबेसडर बने हैं। ये बच्चे अपने अभिभावकों को घरों में गंदगी फैलाने से रोकते हैं और उनसे इधर-उधर गंदगी और कचरा न फैलाने की बात कहते हैं। यदि किसी पिता को गुटका खाने की लत हो, और पिता थूकने के लिए कार की खिड़की खोलता है, तो उसका बेटा भारत को स्वच्छ रखने के ख्याल से पिता को ऐसा करने से रोकता है। इन नन्हे बच्चों के कारण यह कार्यक्रम सफल हुआ है। मैं देश के भविष्य के प्रति शीश झुकाता हूं और इन बच्चों को बधाई देना चाहता हूं।	• मिशन लांच किए जाने के समय से 4.52 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बनाए गए। • 31 जुलाई, 2017 तक 2,17,210 गांवों, 155 जिलो और 5 राज्यों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। • व्यक्तिगत शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 12000 रुपये कर दी गई है। • 02.10.2014 से 02.10.2015 के बीच 80 लाख शौचालय बनाए गए। अनुमान 60 लाख शौचालय बनाने का था। • 2014-15 के लिए 50 लाख व्यक्तिगत शौचालय बनाने का लक्ष्य तय किया गया था और 58,54,987 शौचालय बनाए गए। यह लक्ष्य से 117 प्रतिशत अधिक की उपलब्धि है। • 2012-13 और 2013-14 में क्रमशः 45.59 लाख तथा 49.76 लाख शौचालय बनाए गए। दूसरी ओर एनडीए सरकार के पहले दो वर्षों में यानी 2014-15 तथा 2015-16 (29.02.2015 तक) में क्रमशः 58.54 लाख तथा 97.73 लाख शौचालय बनाए गए।

		• ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के 100 स्वच्छ प्रतीक स्थानों पर विश्व मानकों के अनुरूप उच्च स्तर की स्वच्छता रखी जाएगी। इन स्थानों में से 20 का चयन चरण-1 और चरण-2 में किया गया है। पांच राज्यों के 22 जिलों के गंगा किनारे के 4480 गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया गया।

04	**एलपीजी सब्सिडी छोड़ो योजना** हमने एलपीजी सब्सिडी की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना लागू की। जनधन खातों और आधार कार्ड का लाभ उठाते हुए हमने खातों में सीधे ही सब्सिडी हस्तांतरित की। इसके परिणामस्वरूप ब्रोकर, बिचौलिये और कालाबाजारिए गायब हो गए। इससे केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही लाभ पहुंचा। हमारी सरकार ने किसी के भी खातों से न तो एक भी पैसे की कटौती की और न ही हमने प्रशंसा प्राप्त करने के लिए घोषणाएं की। हमने केवल व्यवस्था में सुधार किया। आज मैं 1.25 बिलियन भारतीयों की टीम इंडिया को यह जानकारी देना चाहता हूं कि इस योजना के परिणामस्वरूप गैस सिलेंडरों के नाम पर प्रति वर्ष साफ की	• सब्सिडी छोड़ो अभियान- लगभग 1.04 करोड़ उपभोक्ताओं ने सब्सिडी छोड़ दी है। (1 मई, 2017 के अनुसार) • गिव बैक- बीपीएल परिवारों को 65 लाख कनेक्शन दिए गए। **प्रधानमंत्री उज्जवला योजना** • बीपीएल परिवारों को 2.16 करोड़ एलपीजी कनेक्शन उपलब्धा कराए गए (1 मई के अनुसार) • इस योजना का पूरे देश में विस्तार हुआ है, अब यह 694 जिलों में लागू है। • 2016-19 के दौरान, तीन वर्षों में पांच करोड़ एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

	जा रही 1500 करोड़ रुपये की राशि रुक गई है। मेरे देशवासियों भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है।	
05.	**प्रति बूंद अधिक फसल** मेरे किसान भाइयों और बहनों पिछले साल पर्याप्त वारिस नहीं हुई। यह जरूरत से कम रही। इसने वर्षा नहीं हुई। यह जरूरत से कम रही इसने अर्थव्यवस्था के साथ-साथ हमारे किसानों को भी प्रभावित किया। हम फिर भी महंगाई को रोकने में समर्थ रहे। हर कोई इस तथ्य को स्वीकार करेगा कि मुद्रा स्फीति दोहरे अंकों में थी। जब हम सत्ता में आए हालांकि वर्षा कम हुई किसान परेशान थे फिर भी हम मुद्रा स्फीति को दोहरे अंकों से 3-4 प्रतिशत पर लाने में सफल रहे। हम इसे और नीचे लाने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे क्योंकि हमारा सपना गरीब से गरीब व्यक्ति को भी संपूर्ण आहार उपलब्ध कराना है। कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की जरूरत है। खेती की जमीन कम हो रही है इसका परिवारों में बंटवारा हो रहा है और जमीन के टुकड़े छोटे होते जा रहे हैं। हमारी कृषि भूमि की उर्वरकता और उत्पादकता बढ़नी चाहिए। किसानों को पानी और बिजली की जरूरत है और हम इन्हें उपलब्ध	**प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)** ● पीएमएसकेवाई के तहत 28.5 लाख हैक्टेयर रकबे को सिंचाई के तहत लाया जाएगा। ● प्रत्येक खेत को पानी उपलब्ध कराने के लिए 5 वर्षों में 50 करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे। ● प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए बजट को 5189 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7377 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ● दीर्घकालीन सिंचाई निधि शतप्रतिशत बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये कर दी गई है। (बजट 2017-18) ● प्रति बूंद अधिक फसल का लक्ष्य अर्जित करने के लिए 5 हजार करोड़ रुपये की राशि के साथ समर्पित सूक्ष्म सिंचाई निधि की स्थापना की गई। ● प्रति बूंद अधिक फसल के तहत सूक्ष्म सिंचाई के लिए 2014 से 2017 तक सूक्ष्म सिंचाई के तहत 17.99 लाख हैक्टेयर भूमि लाई गई।

	कराने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 50 हजार करोड़ रुपये डालने का निर्णय लिया है।	
06.	**ग्रामीण विद्युतीकरण** भाइयों एवं बहनों, आने वाले दिनों में मैं एक मुद्दे पर ध्यान चाहता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक वर्ष बीत चुके हैं लेकिन आज भी देश में लगभग 18 हजार 5 सौ गांव ऐसे हैं जहां बिजली के तार और खम्भे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। 18 हजार 5 सौ गांव आजादी के सूरज से वंचित हैं। वे स्वतंत्रता के प्रकाश से भी महरुम हैं। वे स्वतंत्रता के विकास की किरणों से भी वंचित हैं अगर हम पुराने तरीकों का ही अनुकरण करते रहेंगे तो इन 18 हजार 5 सौ गांवों तक बिजली के खम्भे और तार पहुंचने में कम से कम 10 से अधिक वर्ष लगेंगे। देश इस कार्य के लिए 10 वर्षों तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने सरकार के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई और उनसे इस कार्य के बारे में समय-सीमा के बारे में पूछताछ की। कुछ ने इस कार्य को 2019 तक पूरा करने का वायदा किया तो कुछ ने 2022 तक पूरा करने का आश्वासन दिया। कुछ अधिकारी घने वनों या बर्फ ढकी पहाड़ियों के कारण कुछ बताने में झिझकते रहे। कुछ ने	• विद्युतीकरण किए गए गांव -14033 (76 प्रतिशत) • विद्युतिकरण किए जाने वाले गांव -3453 (19प्रतिशत) • गैर-आबाद गांव - 966 (5 प्रतिशत) • विद्युतीकरण किए गए घर - 13,58,63298 (76 प्रतिशत) • विद्युतीकरण किए जाने वाले घर- 4,31,72,940 (24 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों के विद्युतीकरण में प्रगति की वास्तविक और पारदर्शी ट्रैकिंग के लिए गर्व ॥ ऐप की शुरुआत।

	विशेष क्षेत्रों तक पहुंच न होने के कारण शंका जाहिर की लेकिन अब यह 1.25 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया ने यह शपथ ली है कि इन 18 हजार 5 सौ गांवों तक बिजली के खम्भे, बिजली के तार और बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य अगले 1000 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। मैं, राज्यों से आगे बढ़ने और इस चुनौती को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। यह काम हर राज्य में लंबित नहीं है। केवल कुछ राज्यों को ही इस दिशा में आगे आना होगा। मैं,ऐसे राज्यों के नाम गिनाना नहीं चाहता क्योंकि इसे राजनीतिक रूप से देखा जाएगा और इस पर राजनीतिक टिप्पणियां की जाएंगी। इसलिए इसे नजरअंदाज करना ही बेहतर है। मैं इसलिए 1,25 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया द्वारा लालकिले से शपथ लेने की घोषणा करता हूं कि राज्यों और स्थानीय निकायों की सहायता से इन 18 हजार 5 सौ गांवों को अगले 1000 दिनों में बिजली उपलब्ध करा दी जाएगी।	
07.	**स्टार्टअप इंडिया** भाइयों और बहनों, हमारी युवाशक्ति 21वीं सदी में देश को आगे ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि हमें पूरी दुनिया की तुलना में आगे बढ़ना है तो हमें अपने	• स्टार्टअप इंडिया हब ने टेलीफोन, ई-मेल और ट्विटर के द्वारा स्टार्टअप से प्राप्त लगभग 5700 पूछताछ के समुचित जवाब दिए।

	युवाओं को प्रोत्साहित करना होगा। हमें उन्हें अवसर उपलब्ध कराने होंगे। हमारे युवा कैसे नये उद्यमी बनें कैसे हमारे युवा नये उत्पादक बने और पूरे देश में इन नये उद्यमियों द्वारा स्टार्टअप का पूरा नेटवर्क हो। हिन्दुस्तान का कोई भी जिला कोई भी ब्लॉक ऐसा नहीं होना चाहिए जहां आने वाले दिनों में स्टार्टअप शुरू न किए गए हों। क्या भारत का यह सपना नहीं होना चाहिए कि वह विश्व में स्टार्टअप का पहले नम्बर का देश बन जाए। आज हम इस स्थिति में नहीं हैं। भाइयों और बहनों, मुझे स्टार्टअप को ताकत उपलब्ध करानी है। इसलिए यह मेरा संकल्प है कि आने वाले दिनों में देश के भविष्य के लिए स्टार्टअप इंडिया और स्टैडअप इंडिया होंगे। देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए स्टैंडअप इंडिया की शुरुआत की जाएगी। जब मैं स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया से संबंधित काम के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं तो हमारे देश में बैंक अधिकारियों ने एक बहुत भारी कार्य किया है जब आप अच्छा काम करते हैं तो मेरी उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं।	• स्टार्टअप के लिए एक इंटरैक्टिव शिक्षा एवं विकास मॉड्यूल का शुभारंभ किया गया। ये मॉड्यूल स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। • मान्यता के लिए प्राप्त 2306 आवेदनों के साथ अपेक्षित दस्तावेज लगे थे और इन्हें डीआईपीपी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है। • कर लाभ प्राप्त करने के लिए आईएमबी द्वारा 50 स्टार्टअप को मंजूरी दी गई है। • स्टार्टअप इंडिया हब द्वारा इनक्यूबेशन और वित्तीय सहायता के लिए 410 से अधिक स्टार्टअप को सलाह दी गई। • स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया गया।
08.	**एक रैंक एक पेंशन** प्रधानमंत्री के रूप में पद भार संभालने के बाद मैं यह काम करने के लिए अभी तक समर्थ नहीं हुआ हूं। आज मैं एक बार फिर	• मामले को चार दशकों के बाद सुलझाया गया और प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई। • 30 अप्रैल 2017 के अनुसार (10.07.2017 तक संकलित आंकड़े) 20,39,934 भूतपूर्व सैनिकों/परिवार पेंशनरों और

	सभी सैन्य कर्मियों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यह एक आदमी द्वारा नहीं बल्कि 125 करोड़ लोगों की टीम इंडिया की ओर से ऐसा कह रहा हूं। मैं लाल किले की प्राचीर से तिरंगे के नीचे यह कह रहा हूं। मैं सैन्यकर्मियों से यह कह रहा हूं कि मैंने सैद्धांतिक रूप से एक रैंक एक पेंशन को स्वीकार कर लिया है लेकिन इसके संगठनों के साथ बातचीत चल रही है। यह बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है और पूरे देश के विकास को देखते हुए हम चाहते हैं कि सभी को न्याय मिले। उपरोक्त संदर्भ में हमें पिछले 20-25 सालों से लटके इस समस्या का समाधान ढूढ़ना है। मुझे विश्वास है कि जिस विश्वास के साथ बातचीत हो रही है इसका कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेगा। इसलिए मैं एक बार फिर यह आश्वासन देता हूं कि सरकार ने एक रैंक एक पेंशन को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है। इसकी महत्वपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए कैसे लागू किया जाए। इस बारे में हम इसके हितधारकों को शामिल करके बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं।	1593125 भूतपूर्व सैनिकों को एक रैंक एक पेंशन की बकाया राशि की पहली और दूसरी किस्त के रूप में क्रमश: 4,156.59 करोड़ रुपये और 2385.33 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया। • 15,13,524 भूतपूर्व सैनिकों को एक रैंक एक पेंशन की बकाया राशि की तीसरी किस्त के रूप में 2250.09 करोड़ रुपये की राशि का भी भुगतान किया गया है।

***